बलात्कार के दो .....

पेज एक का शेष

के बहुत से आरोप चर्चा में हैं। जानकार बताते हैं कि फरीदाबाद, गुड़गांव जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर पीएमओ अथवा सिविल सर्जन लगने का रेट पांच लाख तक बताया जाता है। वह बात अलग है कि कोई ज्यादा वजनदार डॉक्टर बिना भारद्वाज के ही ऐसी तैनाती पा ले।

यह बात गले नहीं उतरती कि एक निजी सहायक ही सारा स्वास्थ्य विभाग चला रहा हो। स्वास्थ्य मंत्री विज इतने भोले व नासमझ तो नहीं हो सकते कि वे जानते ही न हों कि उनका निजी सहायक उनके मंत्रालय में क्या खेल खेल रहा है? यदि वे वाकई नासमझ नहीं हैं व सबकुछ उनकी जानकारी व रजामंदी में हो रहा है तो उगाही जाने वाली काली कमाई उन तक भी जरूर पहुंचती होगी। जाहिर है कि जिस मंत्रालय में इस तरह का खुला खेल फरूखाबादी खेला जा रहा हो तो अस्पतालों व डिस्पेंसरियों में डॉक्टर भला क्यों काम करेंगे, क्यों नहीं हर खरीदारी में मोटी-मोटी सेंधमारी करेंगे, क्यों नहीं हर तरह की लूटमारी करके गरीब मरीजों का शोषण करेंगे?

किरण के भी घनिष्ठ सम्बन्ध हैं निजी सहायक कृष्ण से

गतांक में बताया गया था कि एक ठेकेदारी कर्मचारी के रूप में बीके अस्पताल में आई किरण किस प्रकार आज इस अस्पताल में छाई हुई है। जानकार बताते हैं कि उसकी शक्ति का एक बड़ा स्रोत स्वास्थ्य मंत्री विज का निजी सहायक कृष्ण भारद्वाज भी है।

अस्पताल स्टाफ़ के बीच में अक्सर किरण दावा करती है कि भारद्वाज साहब जब भी फरीदाबाद आते हैं तो वे उसी के घर पर रुकते हैं। देखने-सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि इस स्तर का अधिकारी बड़े अफ़सरों की बजाय किरण का आतिथ्य को ज्यादा पसंद करता है। जाहिर है जिसका आतिथ्य भारद्वाज सरीखा अधिकारी स्वीकार करता हो तो अस्पताल में उसकी तूती तो बोलनी ही है, उसके खिलाफ़ चाहे कितने ही आरोप लगते रहें, जांच के नाटक चलते रहें, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।

कर्मचारियों के बीच किरण यह भी कहती बताई गई है कि वीरेन्द्र सांगवान की मुलाकात भी उसी ने भारद्वाज से कराई थी। शायद इसी के बदले किरण व उसके दो साथियों (अमित व देवेन्द्र) को फ़र्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्र गुड़गांव से वीरेन्द्र ने दिलवाये थे। कुल मिला कर देखा जाय तो इस अस्पताल में भ्रष्टाचारियों व हरामखोरों का एक पूरा मकड़जाल बिछा हुआ है। इसके लिये और कोई नहीं स्थानीय शासन-प्रशासन व राजनेता पूरी तरह से जिम्मेवार हैं। यदि ये चाहें तो यह मकड़जाल पलक झपकते ही समाप्त हो सकता है।

Paytm
MM
Majdoor Morcha
UPI ID: 8851091460@paytm
8851091460
Scan this QR or send money to 8851091460 from any app. Money will reach in Majdoor Morcha's bank account.

केवल पाठकों के दम पर चलने वाले इस अखबार को सहयोग देकर अपनी आवाज को बुलंद रखें।

मज़दूर मोर्चा- खाता संख्या- 451102010004150

IFSC Code : UBIN0545112

Union Bank of India, Sector-7, Faridabad

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लबगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड।
2. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
3. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।
4. जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207
5. मोती पाहुजा - मिनार गेट पलवल, 9255029919
6. सुरेन्द्र बघेल-बस अड्डा होडल - 9991742421

हाड़-कंपाऊ ठण्ड में लाखों लोग राशन कार्ड की लाइन में.....

पेज एक का शेष

व्यवसाय-विद्यार्थी, आयु 22 वर्ष, आय -10,000 से 25,000; बाबूलाल पुत्र स्व धुक्कू राम, व्यवसाय- दुकानदार, आयु-45 वर्ष, आय-1,50,000 से 2,50,000 तथा उर्मिला पत्नी बाबूलाल, व्यवसाय- गृहणी, आयु-41 वर्ष, आय 25,000 से 50,000.

विद्यार्थियों अथवा गृहणियों की आय गणना किस आधार पर हुई? अगर ये 'सरकारी' लोग कभी किसी स्कूल- कॉलेज में कभी पढ़ने गए हैं, तो बताएं कि पढ़ते वक़्त, उन्होंने कितने पैसे कमाए और किस विधि से कमाए? उनके घरों में भी गृहणीयां होंगी. उनकी आय कितनी है? आय की रेंज इतनी विशाल है जैसे 25,000 से 50,000 या 1,50,000 से 2,50,000!! जहाँ आय, निश्चित रेखा 1,80,000 से ऊपर जाते ही, अचानक, व्यक्ति के ग़रीब से अमीर बन जाने का ख़तरा हो, और अमीर घोषित होते ही उसका राशन बंद हो जाने का ज़ोखिम हो, वहां आय की इतनी रेंज का क्या मतलब है? प्रशासन के इन मठाधीशों ने कौन सी आय पकड़ी, जिसके आधार पर राशन कार्ड रद्द हुए? आय के इस निर्धारण का आधार क्या है? इन प्रशासनिक शेखचिल्लियों को ये जानने या समझाने की ज़रूरत क्यों महसूस नहीं हुई? न्याय के नैसर्गिक नियम (law of natural justice) के अनुसार, क़ातिलों, बलात्कारियों को भी, अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है. देश के ग़रीब-मज़लूमों को इस लायक भी क्यों नहीं समझा गया कि उनकी आय के अचानक कई गुना बढ़ जाने पर, उन्हें भी अपना पक्ष रखने का अवसर मिले? भरी तोंदों वाले इन 'साहबों' को ऐसी शीत लहर में, अगर बाहर खुले में, दिन भर खड़ा रखा जाए तब शायद इनकी संवेदना जागे, अगर बची हो तो!!

हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के, आय सत्यापित करने वाले अधिकारीयों ने, गुर्बत में सरकारी राशन के भरोसे, किसी तरह अपनी ज़िन्दगी की गाड़ी धकेल रहे, 28.93 लाख लोगों को, हाड़-कंपाऊ ठण्ड में, लाइन में लगा दिया है. कोई जिए या मरे, उन्हें क्या? बर्फ़ीली ठण्ड से बचने के लिए अपने घरों में दुबके बैठे, मनरेगा मज़दूरों, दिहाड़ी मज़दुरों, रेहड़ी-पटरी पर दो जून रोटी का जुगाड़ करने वाले लोगों के मोबाइल पर अचानक दिल दहलाने वाले संदेशे आने शुरू हो गए, 'आपकी वार्षिक आय 1,80,000/ से आगे निकल गई, आप ग़रीबी रेखा से ऊपर उठ गए, आपका राशन कार्ड रद्द हो चुका है'. रजाई में बैठे-बठे, अचानक ग़रीबी से उठकर अमीरी में पहुंचे लोग, चकरा गए. ये हादसा कैसे हुआ!! इनकम जांचने वाले शेखचिल्लियों ने, इन संदेशों को पढ़ने की भी ज़हमत नहीं उठाई. 'पंकज, पेशा-छात्र, आय 70,000 प्रति वर्ष!'; 'कुसुम, पेशा-गृहणी, आय-80,000/ प्रति वर्ष!!' कोई पढ़कर भले हार्ट अटैक से मर जाए, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है?? उनके और उनके आक़ाओं के तो पेट भरे हैं और दफ़्तर में हीटर चालू हैं.

हरियाणा सरकार का खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, नागरिकों को 3 तरह के राशन कार्ड ज़ारी करता है. ग़रीबी रेखा (1,80,000/ रु) से ऊपर के नागरिकों के लिए, APL इस कार्ड का रंग पिंक है और दूसरे राज्यों से विस्थापित होकर हरियाणा आए व्यक्ति भी इस कार्ड के हक़दार हैं. उनके पैत्रिक राज्य में यदि उन्हें ग़रीबी रेखा से नीचे वाला कार्ड जारी हुआ है, और उन्हें वहां राशन कार्ड मिल रहा है तो 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना के तहत, उनकी पात्रता के अनुसार सस्ता राशन मिलेगा. अगर ऐसा नहीं है तो इस समूह के लोगों को सस्ता राशन कार्ड नहीं मिलेगा.

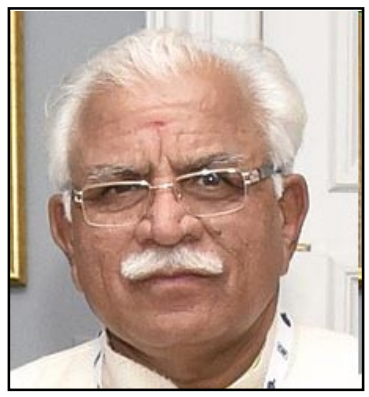

ग़रीबी रेखा से नीचे वाले नागरिकों के लिए, BPL- वह परिवार जिसकी वार्षिक आय 1,80,000/ से कम है, उसे पीले रंग का ये बीपीएल कार्ड ज़ारी होता है और साल में 1 लाख से भी कम कमाने वाले, समाज के अत्यंत निर्धन समूह के लिए, लाल रंग का 'अन्त्योदय कार्ड' ज़ारी होता है. इन कार्ड धारकों को, सस्ते गल्ले की आधिकारिक मासिक पात्रता इस तरह है- 2 रु प्रति किलो की दर से 5 किलो गेहूँ, 13.5 रु प्रति किलो की दर से 2 किलो चीनी, 13.63 प्रति लीटर की दर से 7 लीटर मिट्टी का तेल, 20 रु प्रति किलो की दर से 2.5 किलो दाल. सरसों का तेल भी मिला करता था लेकिन जैसे ही उसका रेट 200/ प्रति किलो के पार पहुंचा, उसकी आपूर्ति बंद हो गई. इतने मंहगे तेल की ग़रीबों को क्या ज़रूरत!! ज़मीनी हक़ीक़त ये है कि गेहूं या चावल के आलावा कुछ भी नहीं मिलता.

राशन कार्ड महज़ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है. हमारे देश में ये, करोड़ों लोगों की श्वास नली है. इसके रद्द होने का मतलब है, छत्तीसगढ़ की वो बच्ची, जो भात-भात बुदबुदाते हुए मर गई, क्योंकि उनका राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होने के कारण, उस परिवार को राशन देने से मना कर दिया गया था. सारा देश वो हकीक़त इसलिए जान पाया, क्योंकि एक साहसी पत्रकार उस तथ्य को देश के सामने लाया. 'विश्व गुरु' भारत में, जाने कितने मासूम, मज़लूम, बाज़ार भाव से, अपने जीने लायक़ अन्न ना ख़रीद पाने की वज़ह से धीमी मौत मरते जा रहे हैं. केन्द्रीय खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री, संसद में ये स्वीकार कर ही चुकी हैं कि 2018 से 2020 के बीच, 3 सालों में, देश में करोड़ों 'फ़र्ज़ी' राशन कार्ड रद्द हुए. उस दौरान, हरियाणा में कुल 3.91 लाख राशन कार्ड रद्द हुए.

मूल प्रश्न ये है कि देश में, अगर इतनी बड़ी तादाद में फ़र्ज़ी राशन कार्ड बने, तो ये एक अत्यंत गंभीर घोटाला है. इसकी ज़िम्मेदारी तय होनी चाहिए थी. सबसे पहले तो 'माननीय' मंत्री जी को ही बर्खास्त किया जाना चाहिए था. हज़ारों की संख्या में उन अधिकारियों और उनके लगुए-भगुओं को जेलों में डाला जाना चाहिए था जिन्होंने फर्जी राशन कार्ड बनाने का गोरखधंधा चलाया. जब मर्ज़ी राशन कार्ड बना दिए, जब मर्ज़ी रद्द कर दिए; ये बहुत अमानवीय, क्रूर मज़ाक़ है जिसकी ज़िम्मेदारी तय होनी चाहिए. सरकार सब जानती है, अगर नहीं जानती तो जान ले, कि फ़र्ज़ी राशन कार्ड बनाने का काम रसूखदार लोग करते हैं. उनके बनाए कार्ड रद्द भी नहीं होते. रद्द तो ग़रीबों के ही कार्डों को होना पड़ता है. पिछले तीन सालों में भी यही हुआ और आज भी वही होगा.

मोदी सरकार की कुछ चारित्रिक विशिष्टताएं हैं, जिसे अब लोग समझते जा रहे हैं. ये सरकार, आज तक आई सरकारों में सबसे ज्यादा मज़दूर-विरोधी और मज़लूम-विरोधी है. दूसरी ख़ासियत ये है कि इसके काम करने का तरीका 'झांसेबाज़ी' वाला है. सारे मंत्री-संत्री घोषणावीर हैं. राज्य सरकारें, स्वाभाविक रूप से केंद्र सरकार का अनुकरण करती हैं. 'डबल इंजन' वाली तो हू-ब-हू करती हैं. ढोल-ढमाकों के साथ ऊँची-ऊँची घोषणाएँ करो, मीडिया द्वारा उसे एक 'ऐतिहासिक इवेंट' बनाओ और भूल जाओ!! बिना तथ्यों को जांचे-परखे, एकदम लहरीपने से, ग़रीबों की आय, कागजों में बढाओ. इससे, एक तो ग़रीब, ग़रीबी रेखा से ऊपर उठ जाएँगे और दूसरे उनके राशन कार्ड रद्द हो जाएँगे. इस वक़्त की सबसे रसीली घोषणा, मोदी जी द्वारा, ये की गई है कि 81.6 करोड़ लोगों को सरकार मुफ़्त अनाज देगी. सब जानते हैं कि ये झांकी अगले लोकसभा चुनावों तक जमाई जाएगी. सरकार की असल मंशा जानना कोई राकेट साइंस नहीं. उसकी नीयत है कि दुनियाभर में मोदी सरकार की ग़रीबपरस्ती का डंका बजे, देश के लोग 2024 के चुनावों में मुफ्त राशन की ख़ुमारी में अपने सब दुःख दर्द भूलकर झूम जाएँ और फिर से उसी सरकार को चुनें, जो चंद कॉर्पोरेट के मुनाफ़े के लिए ग़रीब-गुरबा को बेरहमी से निचोड़ रही है और पल्ले से कुछ जाए भी ना. राशन कार्ड रद्द कर अनाज बचाओ और उसे खैरात के रूप में बांटो और तालियाँ समेटो!!

कोरोना महामारी में जब लोगों के सामने महामारी से भी ज्यादा भुखमरी से मरने की नौबत आ गई थी, तब अप्रैल 2020 में मोदी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ़्त अनाज देने की घोषणा की थी. ये बात सब जानते हैं. वह योजना बंद हो गई, ये कितने लोगों को मालूम पड़ा? अब फिर, 81.6 करोड़ लोगों को मुफ़्त अनाज देने की घोषणा हुई और पालतू मीडिया के गले का पट्टा खोल दिया गया. देशभर में कानफाड़ू शोर मच गया और अखबारों में दरबारी पत्रकारों के, मोदी सरकार की दरियादिली के लम्बे-लम्बे लेख छप गए. दूसरी ओर, करोड़ों लोगों की आय अधिक बताकर,1 जनवरी से उनका राशन बंद करने की चेतावनी ज़ारी हुई. पालतू मीडिया में कहीं कोई आवाज़ सुनाई पड़ी? हिटलर के प्रोपेगंडा मंत्री, गोएबेल ने ऐसे ही नहीं कहा था, "मुझे कुछ दिन के लिए मीडिया सौंप दो और मैं पूरे देश को सूअरों के झुण्ड में बदल डालूँगा'!! आज के गोएबेल और आज का मीडिया उस वक़्त से कहीं अधिक काइयां हैं.

जिन्हें कार्ड रद्द होने के नोटिस मिले हैं, उनमें से कितने लोग, अपनी दिहाड़ी गंवाकर, राशन कार्ड दुरुस्त कराने की अनंत लाइन में लगकर, अपने राशन कार्ड बचा पाएंगे और कितने हाय सी मारकर बैठ जाएँगे, किसे मालूम? हर ज़िले के लघु सचिवालयों पर हड़कंप मचा हुआ है. भीषण ठण्ड में दिनभर खड़े रहकर, बेक़सूर ग़रीब लोग बीमार पड़ रहे हैं. अफ़रा-तफ़री मची हुई है. कई जगह, इन बेहाल लोगों के 'पेशेवर मददगार' प्रकट हो गए हैं, जो 'काम तो हो जाएगा, कुछ खर्च करना पड़ेगा', कहकर लोगों को ठग रहे हैं. राशन कार्ड में अनुचित आमदनी दर्ज कराने वाले अफ़सरान और उनके आक़ा असल क़सूरवार हैं. उन्हें दंडित किया जाना चाहिए. इस पूरे के पूरे फ़रमान को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए. कहीं किसी राशन कार्ड में वाक़ई ग़लती है तो उसे ज़रूर दुरुस्त किया जाना चाहिए.

गर राशन कार्ड वाक़ई फ़र्ज़ी है, तो उसे रद्द किया जाए लेकिन उसे बनाने वाले कर्मचारी- अधिकारी को भी बरखाश्त कर, गिरफ्तार किया जाए. ग़रीबों-मेहनतक़शों को थोड़ी भी सम्मानपूर्ण ज़िन्दगी जीने की ख्वाहिश है तो उन्हें संगठित हो संघर्ष करने के सिवा पर्याय नहीं.